नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 222
दि. 16.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

उत्तर बंगाल से उठी नई राजनीतिक आवाज, रथिंद्र बोस बने विधानसभा अध्यक्ष; पहली बार विधायक बनते ही मिला सबसे बड़ा संवैधानिक दायित्व

पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब भाजपा नेता रथिंद्र बोस को निर्विरोध पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। यह केवल एक संवैधानिक नियुक्ति भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राज्य की बदलती राजनीतिक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन का बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। खास बात यह रही कि रथिंद्र बोस पहली बार विधायक बने हैं और विधानसभा में पहली बार प्रवेश करते ही उन्हें सदन की सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंप दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह फैसला भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति और उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब उत्तर बंगाल से आने वाला कोई नेता पश्चिम बंगाल विधानसभा का अध्यक्ष बना है। यही कारण है कि इस फैसले को केवल राजनीतिक नियुक्ति नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। भाजपा ने कूचबिहार दक्षिण से विधायक रथिंद्र बोस को 18वीं विधानसभा के स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। विपक्षी All India Trinamool Congress ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके बाद उनका निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया था।

विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जबकि प्रोटेम स्पीकर तपस रॉय ने ध्वनिमत से उनके निर्वाचन की घोषणा की। सदन में इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर उनका स्वागत किया और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण क्षण बताया।

रथिंद्र बोस का जीवन सफर भी काफी दिलचस्प और प्रेरणादायक माना जा रहा है। उनका जन्म कूचबिहार जिले के देबीबारी इलाके में हुआ। शुरुआती शिक्षा कूचबिहार में पूरी करने के बाद उन्होंने बीटी एंड इवनिंग कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने

चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पूरी की। पेशेवर जीवन में उन्होंने बड़ी उपलब्धि तब हासिल की जब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय परीक्षा में पांचवां स्थान प्राप्त किया।

शिक्षा और पेशेवर सफलता के बाद उनका सफर विदेश तक पहुंचा। कुछ वर्षों तक वे लंदन में भी रहे, लेकिन बाद में भारत लौट आए और उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में बस गए। विदेश में रहने और पेशेवर करियर के बावजूद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से दूरी नहीं बनाई।

लंदन से लौटने के बाद रथिंद्र बोस धीरे-धीरे Rashtriya Swayamsevak Sangh और भाजपा की संगठनात्मक राजनीति से सक्रिय रूप से जुड़ गए। उत्तर बंगाल में संगठन विस्तार और कार्यकर्ता नेटवर्क मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वे लंबे समय तक भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य महासचिव जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में वे भाजपा के उत्तर बंगाल संगठनात्मक संभाग के संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। पार्टी के भीतर उनकी पहचान एक शांत, संगठित और वैचारिक रूप से मजबूत नेता के रूप में रही है।

उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी भाजपा संगठन से गहराई से जुड़ी हुई है। उनके छोटे भाई बिराज बोस भी भाजपा में सक्रिय हैं और फिलहाल कूचबिहार जिले में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भाजपा ने इस नियुक्ति के जरिए उत्तर बंगाल को विशेष राजनीतिक महत्व देने का प्रयास किया है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर बंगाल भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र बनकर उभरा है। पार्टी लगातार इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले निशीथ प्रमाणिक को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल कर उत्तर बंगाल विकास, खेल और युवा मामलों का विभाग सौंपा गया था। अब रथिंद्र बोस को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने इस क्षेत्र को एक और बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद केवल सदन की कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह संवैधानिक संतुलन, राजनीतिक निष्पक्षता और संसदीय परंपराओं की रक्षा से भी जुड़ा होता है। आमतौर पर यह जिम्मेदारी किसी अनुभवी विधायक को दी जाती है, जिसे सदन की प्रक्रियाओं का लंबा अनुभव हो। लेकिन भाजपा ने इस बार परंपरा से हटकर पहली बार विधायक बने नेता पर भरोसा जताया है।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सदन में उनके नाम का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि रथिंद्र बोस केवल संगठन के समर्पित कार्यकर्ता ही नहीं हैं, बल्कि उनकी शैक्षणिक और प्रशासनिक समझ भी बेहद मजबूत है। उन्होंने विश्वास जताया कि बोस सदन की गरिमा बनाए रखते हुए सभी दलों के बीच संतुलन कायम रखेंगे।

अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि पहली बार विधायक बने रथिंद्र बोस विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका किस तरह निभाते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय से तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और आक्रामक बहसों के लिए जानी जाती रही है। ऐसे में सदन की कार्यवाही को संतुलित और व्यवस्थित ढंग से चलाना उनके लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

फिलहाल उनके निर्वाचन को भाजपा के संगठनात्मक विस्तार, उत्तर बंगाल की बढ़ती राजनीतिक अहमियत और नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे लाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह फैसला आने वाले वर्षों में दूरगामी असर डाल सकता है।

मोटापे और दिमागी बीमारियों के बीच बढ़ता वैज्ञानिक संबंध, अल्जाइमर के खतरे पर नई चेतावनी

नई वैज्ञानिक रिसर्च में एक अहम और चिंताजनक बात सामने आई है कि शरीर में बढ़ता मोटापा केवल शारीरिक समस्याओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सीधे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में यह संकेत मिले हैं कि मोटापे के कारण शरीर में होने वाले जैविक बदलाव मस्तिष्क तक ऐसे हानिकारक संकेत पहुंचा सकते हैं, जो आगे चलकर न्यूरोलॉजिकल बीमारियों, खासकर अल्जाइमर रोग के खतरे को बढ़ा सकते हैं।

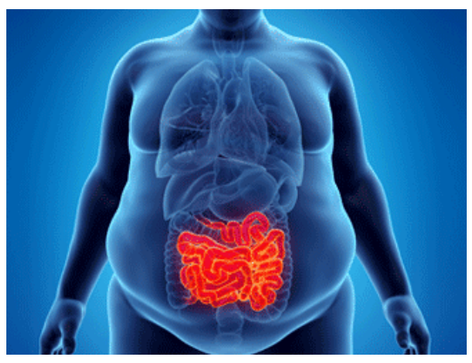

यह अध्ययन अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल मॉलिक्यूलर न्यूरोडीजेनेरेशन में प्रकाशित हुआ है, जिसमें शोधकर्ताओं ने मोटापे और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारियों के बीच संभावित जैविक संबंधों का गहराई से विश्लेषण किया है। शोध के अनुसार, शरीर में जमा अतिरिक्त वसा (फैट) केवल ऊर्जा का भंडार नहीं होती, बल्कि यह सक्रिय रूप से हार्मोन और रासायनिक संकेतों को प्रभावित करती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों, विशेष रूप से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं।

शोधकर्ताओं का कहना है कि मोटापे की स्थिति में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) असंतुलित हो सकती है। यह असंतुलन मस्तिष्क की प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली को भी कमजोर कर सकता है, जिससे न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

अध्ययन में यह भी पाया गया कि मोटापे से जुड़े जैविक परिवर्तन मस्तिष्क में अमाइलॉइड प्रोटीन के जमाव को बढ़ा सकते हैं, जो आगे चलकर तंत्रिका कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार, अल्जाइमर रोग एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे व्यक्ति की याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और व्यवहारिक संतुलन को प्रभावित करती है। समय के साथ यह स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि व्यक्ति अपनी दैनिक गतिविधियों को भी ठीक से करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए इसे केवल उम्र बढ़ने से जुड़ी सामान्य समस्या मानना गलत होगा, क्योंकि अब इसमें जीवनशैली और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य की भूमिका भी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है।

इस अध्ययन में अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित एक प्रमुख मेडिकल संस्थान के शोधकर्ताओं ने योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि मोटापा केवल शरीर के बाहरी हिस्सों पर असर नहीं डालता, बल्कि यह मस्तिष्क के अंदर सूक्ष्म स्तर पर भी बदलाव पैदा कर सकता है। इन बदलावों के कारण मस्तिष्क की इम्यूनिटी प्रणाली कमजोर पड़ सकती है और सूजन (inflammation) जैसी प्रक्रियाएं सक्रिय हो सकती हैं, जो न्यूरॉन्स के लिए हानिकारक होती हैं।

शोध के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक ने बताया कि यह समझना जरूरी है कि शरीर में जमा वसा निष्क्रिय नहीं होती, बल्कि यह लगातार रासायनिक संकेत छोड़ती रहती है। ये संकेत मस्तिष्क तक पहुंचकर उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह अपरिवर्तनीय नहीं है और शुरुआती चरण में जीवनशैली में बदलाव और चिकित्सीय हस्तक्षेप से इसे नियंत्रित किया जा सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में मोटापे की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण यह स्थिति और गंभीर होती जा रही है। यदि इस दिशा में समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले वर्षों में अल्जाइमर जैसी बीमारियों के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है।

चिकित्सा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और वजन नियंत्रण केवल हृदय या मधुमेह जैसी बीमारियों के लिए ही नहीं, बल्कि मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। यह अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि शरीर और मस्तिष्क के बीच संबंध पहले से कहीं अधिक गहरा और जटिल है।

कुल मिलाकर यह शोध एक महत्वपूर्ण चेतावनी के रूप में सामने आया है कि मोटापा केवल एक शारीरिक समस्या नहीं है, बल्कि यह धीरे-धीरे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जीवनशैली में सुधार और जागरूकता इस दिशा में सबसे प्रभावी उपाय माने जा रहे हैं।

ईंधन महंगाई पर सियासी घमासान तेज, कांग्रेस ने सरकार को घेरा, जनता पर बढ़ते बोझ का आरोप

देश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। विपक्षी दल Indian National Congress ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि आम जनता को लगातार महंगाई और आर्थिक दबाव की मार झेलनी पड़ रही है, जिसका मुख्य कारण सरकार की नीतिगत गलतियां और कथित आर्थिक अदूरदर्शिता है।

कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईंधन की कीमतों में वृद्धि कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि यह लंबे समय से चली आ रही आर्थिक नीतियों का परिणाम है। पार्टी का कहना है कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं, तब भी जनता को उसका पूरा लाभ नहीं दिया गया, और अब जब वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उसका सीधा बोझ आम लोगों पर डाला जा रहा है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बढ़ोतरी जनता के लिए एक और आर्थिक झटका है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों का असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है और आगे भी किस्तों में इस तरह की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राहुल गांधी ने इसे "गलत नीतियों की

कीमत जनता द्वारा चुकाना" बताया और सरकार की आर्थिक रणनीति पर सवाल उठाए।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा आर्थिक दबाव सरकार की नीतिगत विफलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद सरकार ने समय रहते कोई ठोस रणनीति नहीं अपनाई।

खरगे ने यह भी कहा कि सरकार ने जनता की चिंताओं को नजरअंदाज किया और चुनावी माहौल को देखते हुए स्थिति को सामान्य दिखाने की कोशिश की। अब जब कीमतों में वृद्धि हो रही है, तो सरकार ईंधन बचाने और वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों को बढ़ावा दे रही है, जिसे विपक्ष ने "देर से उठाया गया कदम" बताया है।

कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि आर्थिक प्रबंधन में पारदर्शिता और दूरदर्शिता की कमी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि जब वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें कम थीं, तब सरकार ने करों और शुल्कों में राहत नहीं दी, जिससे आम जनता को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया।

पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर देश को ऐसी स्थिति में क्यों लाया गया है, जहां अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी निर्णयों के लिए बाहरी देशों पर निर्भरता बढ़ती दिखाई दे रही है। कांग्रेस का दावा है कि यह स्थिति आर्थिक आत्मनिर्भरता की बजाय आर्थिक दबाव और असंतुलन को दर्शाती है।

दूसरी ओर, सरकार की ओर से यह तर्क दिया जाता रहा है कि ईंधन की कीमतें वैश्विक बाजार, कच्चे तेल की दरों और कर संरचना पर निर्भर करती हैं, और राज्यों की टैक्स नीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर परिवहन लागत, खाद्य वस्तुओं की कीमतों और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर पड़ता है, जिससे महंगाई का व्यापक असर देखने को मिलता है। ऐसे में यह मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आम जनता की आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है।

फिलहाल, Indian National Congress इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि सत्ता पक्ष इसे वैश्विक परिस्थितियों और बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का परिणाम बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद और राजनीतिक मंचों पर और अधिक गर्माने की संभावना है।

आरजी कर मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई, पश्चिम बंगाल सरकार ने तीन आईपीएस अधिकारियों को किया निलंबित

पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में एक बार फिर बड़ा भूचाल देखने को मिला है, जब राज्य सरकार ने तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला लिया। यह कार्रवाई जिस मामले से जुड़ी है, वह पहले से ही पूरे देश में संवेदनशील और चर्चित रहा है—आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म-हत्या मामला। इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि पुलिस प्रशासन की शुरुआती कार्यशैली और जांच प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर विवाद पैदा किया था। अब ताजा निलंबन ने इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है।

सरकारी आदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उप-आयुक्त इंदिरा मुखर्जी और अधिकारी अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। इन तीनों पर आरोप है कि उन्होंने मामले की शुरुआती जांच के दौरान अपेक्षित संवेदनशीलता, निष्पक्षता और तत्परता नहीं दिखाई, जिससे जांच की दिशा और विश्वसनीयता पर सवाल उठे। राज्य सरकार का कहना है कि यह मामला सामान्य प्रशासनिक चूक का नहीं बल्कि गंभीर कर्तव्य लापरवाही का है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे जांच तंत्र पर

जनता का भरोसा प्रभावित हुआ।

सरकारी सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई अचानक नहीं की गई, बल्कि लंबे समय से चल रही आंतरिक समीक्षा और शिकायतों के आधार पर यह निर्णय लिया गया। आरोप यह भी है कि जांच के शुरुआती चरण में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ठीक से दर्ज नहीं किया गया और कुछ प्रक्रियागत खामियां सामने आईं, जिनका असर आगे की जांच पर पड़ा। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि कुछ संवेदनशील सूचनाओं के प्रबंधन में गंभीर अनियमितताएं हुईं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई।

सबसे गंभीर आरोपों में यह दावा भी शामिल है कि कुछ अधिकारियों ने पीड़िता के परिजनों से संपर्क के दौरान कथित रूप से आर्थिक प्रलोभन या रिश्वत जैसी पेशकश की थी, जिसे प्रशासन ने अत्यंत गंभीर अनुशासनहीनता माना है। इसके साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि मामले के दौरान एक अनाधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आधिकारिक अनुमति या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसे सेवा नियमों का सीधा उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों में मीडिया ब्रीफिंग पूरी तरह नियंत्रित और अधिकृत प्रक्रिया के तहत ही की जानी चाहिए।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। यह जांच न केवल उनके व्यक्तिगत आचरण पर केंद्रित होगी, बल्कि इस बात की भी समीक्षा करेगी कि जांच प्रक्रिया में कौन-कौन से निर्णय लिए गए और किन स्तरों पर प्रशासनिक चूक हुई। सरकार का कहना है कि यह कदम किसी राजनीतिक दबाव या बाहरी प्रभाव में नहीं लिया गया है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और संस्थागत सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है।

इस पूरे घटनाक्रम में Central Bureau of Investigation की चल रही जांच को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह सीबीआई की जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रही है और आपराधिक जांच को पूरी तरह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया जा रहा है। निलंबन की यह कार्रवाई केवल विभागीय और अनुशासनात्मक दायरे में है, जिसका उद्देश्य पुलिस प्रशासन की आंतरिक जवाबदेही तय करना है।

घटना का केंद्र कोलकाता रहा है, जहां इस मामले ने व्यापक जनाक्रोश और सामाजिक चिंता को जन्म दिया था। यह मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह पुलिस प्रशासन, अस्पताल सुरक्षा व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न बन गया है। कई नागरिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मामले को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा उदाहरण बताया है, जिसमें शुरुआती प्रशासनिक विफलता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया।

राजनीतिक स्तर पर भी इस कार्रवाई के दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। विपक्षी दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं और इसे देर से लिया गया कदम बताया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह कार्रवाई यह दिखाती है कि सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति को फिर से गरमा दिया है और आने वाले दिनों में यह विवाद और तेज होने की संभावना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में शुरुआती 24 से 72 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उसी दौरान साक्ष्य, गवाह और घटनास्थल की स्थिति सबसे अधिक निर्णायक होती है। यदि इस चरण में किसी प्रकार की चूक होती है, तो पूरा केस प्रभावित हो सकता है। इसी कारण इस मामले में उठाए गए सवाल प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करते हैं।

अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि विभागीय जांच में क्या निष्कर्ष निकलते हैं और क्या इन अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल निलंबन तक सीमित रहती है या आगे और सख्त कार्रवाई भी होती है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म-हत्या मामला की सीबीआई जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या उसमें नए तथ्य सामने आते हैं।

फिलहाल यह पूरा मामला राज्य प्रशासन, पुलिस तंत्र और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन की एक बड़ी परीक्षा बन चुका है, जिसका असर आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीतिक माहौल दोनों पर लंबे समय तक महसूस किया जा सकता है।

संपादकीय

महिला सुरक्षा पर दिल्ली बार-बार

चौदह साल पहले दिल्ली में जिस निर्भया कांड ने भारत की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था, दिल्ली में एक बार फिर उस जैसी त्रासदी की पुनरावृत्ति हुई है। दिल्ली ने एक बार फिर इस भयावह सच का सामना किया किया है कि वहां की सार्वजनिक जगहें महिलाओं के लिये कितनी असुरक्षित व भयावह बनी हुई हैं। दुर्भाग्य से एक बार फिर वही बस अपराध स्थली बनी है, जो सार्वजनिक आवागमन और सुरक्षा के लिये बनी होती हैं। दिल्ली स्थित नांगलोई में एक प्राइवेट स्लीपर बस के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा एक महिला के साथ कथित रूप से गैंगरेप की घटना ने सभ्य समाज को गहरे तक विचलित किया है। इस घटना ने एक बार फिर से शासन-प्रशासन, पुलिसिंग और परिवहन नियमों के पालन में हुई भारी चूक का एक जीता-जागता सबूत पेश किया है। निस्संदेह, इस घटना की क्रूरता केवल उस हमले में ही नहीं है, बल्कि उत्पन्न परिस्थितियों की भयानक रूप में जानी-पहचानी प्रकृति में भी है। विडंबना देखिए कि जिस बस को महिलाएं सार्वजनिक यातायात के लिये सुरक्षित मानकर चलती हैं, उसी में यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। एक बार फिर बस अपराधियों के मंसूबों को पूरा करने वाला साधन बनी। इस घटना ने एक बार फिर से उजागर किया है कि जिन लोगों को यात्रियों के सुरक्षित आवागमन की जिम्मेदारी दी गई थी, वे ही कथित तौर पर दरिंदे बनकर सामने आए। हर बार की तरह तुरंत कार्रवाई का दावा करते हुए गिरफ्तारी को तत्काल कदम उठाने के रूप में दर्शाया जा रहा है। जबकि एक हकीकत है कि हमारी व्यवस्था की विद्रूपताएं जस की तस बनी हुई हैं। सही मायनों में देश के हृदय में वर्ष 2012 के जख्म अभी भरे नहीं हैं। विडंबना देखिए कि निर्भया कांड के बाद सरकारों ने तमाम सुधारों के वायदे जनता के सामने किए थे। तब घोषणा की गई थी कि अपराधियों पर नजर रखने के लिये दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को व्यापक रूप दिया गया है। लेकिन परिणाम जस के तस रहे।

देश को याद है कि वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद त्वरित फैसले लेने वाली अदालतों की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। इसके अलावा महिला सुरक्षा से जुड़ी तमाम योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये व्यापक प्रचार किया गया था। इसके बावजूद एक और निर्भया जैसी घटना बताती है कि अब तक जमीनी हकीकत में बहुत कुछ बदलाव नहीं आया है। देखने में आया है कि तमाम निजी बसें अपर्याप्त निगरानी व लचर सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलती रहती हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल का पालन अक्सर महज दिखावे के लिये होता है। निस्संदेह, निजी बसों के कर्मचारियों की सख्त जांच के अभाव ने ऐसे वातावरण को तैयार किया है जहां चालक-परिचालक व अन्य अपराधियों की समांतर गुंडागर्दी चलती रहती है। यही वजह है कि गाहे-बगाहे दिल्ली की छवि महिलाओं के लिये असुरक्षित शहर होने के कारण खराब हुई है। जिसका कारण है कि यहां जवाबदेही संस्थागत होने के बजाय सतही तौर पर नजर आती है। यह विडंबना ही है कि हर बार ऐसी घटना के बाद जन आक्रोश में उबाल आता है। लेकिन देखने में आता है कि जल्दी ही राजनीतिक बयानबाजी और कालांतर नौकरशाही की उदासीनता में बदल जाता है। यही वजह है कि महिलाएं इस भय को अपनी नियति मानकर जीने को अभिशप्त हैं। दिल्ली की जागरूक जनता को चाहिए कि वे नांगलोई की घटना को महज एक और गुजरती सुर्खी बनकर न रहने दें। उन्हें इसे ऐसे अपराधों को रोकने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बनाना चाहिए। निस्संदेह, दिल्ली के अधिकारियों को निजी परिवहन संचालकों की व्यापक जांच-पड़ताल करनी चाहिए। जिसमें रियल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग को निजी बसों में अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। साथ ही निजी बस चालक व परिचालकों की पृष्ठभूमि की कड़ी जांच करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह कि सरकारों को समझ लेना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा महज बयानबाजी व नारे लगाने से सुनिचित नहीं होगी। साथ ही शासन-प्रशासन को घटना के बाद पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए। बल्कि अपराध नियंत्रण की दिशा में भी गंभीर पहल होनी चाहिए।

ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के 'दिल्ली-विमर्श' के निहितार्थ

"देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल है। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है।"

ब्रिक्स (BRICS) के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय दिल्ली बैठक ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक संदेश दिए हैं, जिनके कूटनीतिक निहितार्थ को समझने की जरूरत है। अन्यथा शेष दुनिया को अमेरिकी-यूरोपीय दादागिरी (नाटो सैन्य गठबंधन) के दुनियावी दांवपेंचों से निजात मिलनी मुश्किल है। लिहाजा, इस बैठक में मुख्य रूप से वैश्विक शक्ति-संतुलन, अमेरिकी प्रतिबंध नीति, पश्चिम एशिया संकट, वैश्विक व्यापार व्यवस्था और "ग्लोबल साउथ" की भूमिका पर जोर दिखाई दिया। देखा जाए तो नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है। दो दिनों का यह 18वां शिखर सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब दुनिया कई मोर्चे पर अस्थिरता से गुजर रही है। ब्रिक्स के सदस्य देश - ईरान और यूएई सीधे तौर पर इस हलचल में शामिल है। ऐसे में यह जुटान पूरी दुनिया के लिए अहम हो जाती है। इस अहम बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्जेइ लावरोव और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची जैसे नेताओं के दूरदर्शिता भरे बयान विशेष चर्चा में रहे। जिसके दुनियावी मायने बेहद अहम हैं।

जिस तरह से कूटनीतिक सम्मेलन के पहले ही दिन जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ लगाए जाने वाले एकतरफा प्रतिबंधों का जिक्र किया, जो सबसे ज्यादा विकासशील देशों को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वाभाविक तौर पर उनका इशारा अमेरिका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की वजह से दुनिया को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं, ईरान मामले में भी गतिरोध की वजह बहुत हद तक वॉशिंगटन की अव्यवहारिक मांगें है। ब्रिक्स के बड़े मंच

से उठी आवाज का असर ज्यादा होगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर का उद्घाटन भाषण मौजूदा चुनौतियों का सही खाका खींचता है। पश्चिम एशिया पर मंडराता युद्ध का खतरा, ऊर्जा संकट, सप्लाई चेन में रुकावट और जलवायु परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। तमाम देशों की अर्थव्यवस्था को मंदी में फंसने का डर सता रहा है। ऐसे में जैसा कि विदेश मंत्री ने कहा, विकासशील देशों ने ब्रिक्स से यह उम्मीद लगाई है कि यह मंच स्थिरता कायम करने में सकारात्मक भूमिका अदा करेगा। इसके कतिपय निहितार्थ इस प्रकार हैं-

पहला, एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौतीः बैठक का सबसे बड़ा संदेश यह था कि दुनिया अब केवल अमेरिका-केन्द्रित व्यवस्था पर निर्भर नहीं रहना चाहती। ब्रिक्स देशों ने "मल्टीपोलर वर्ल्ड" के दृष्टिगत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका अर्थ है कि वैश्विक निर्णयों में पश्चिमी देशों के साथ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की शक्तियों की भी बराबर भूमिका हो।

दूसरा, अमेरिकी प्रतिबंधों और आर्थिक दबाव का विरोधः भारत, रूस, चीन और ईरान सहित कई देशों ने एकतरफा प्रतिबंधों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और संप्रभुता के खिलाफ बताया। विशेष रूप से एस जयशंकर ने कहा कि प्रतिबंध और दबाव कूटनीति का विकल्प नहीं हो सकते। यह संदेश सीधे तौर पर अमेरिका की प्रतिबंध नीति की आलोचना माना गया।

तीसरा, डॉलर प्रभुत्व कम करने का संकेतः बैठक में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर भी चर्चा हुई। यह संदेश था कि ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहते हैं ताकि अमेरिकी आर्थिक दबाव का असर घटाया जा सके।

चतुर्थ, पश्चिम एशिया संकट पर चिंताः ईरान-इज़राइल तनाव और समुद्री मार्गों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहा। ब्रिक्स देशों ने रेड सी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे मार्गों की सुरक्षा पर जोर दिया। दुनिया को यह संदेश दिया गया कि क्षेत्रीय युद्ध अब वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि इस मंच के सामने भी चुनौती है। ईरान और यूएई के आपसी रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जबकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा है। एक बात और, जब सम्मेलन की शुरुआत हुई, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग तब ट्रंप की मेजबानी में व्यस्त थे। ब्रिक्स के सबसे बड़े विरोधी ट्रंप है। उन्हें लगता है कि यह मंच अमेरिकी हितों के खिलाफ खड़ा किया गया है। मेजबान होने के नाते यह भारत की जिम्मेदारी है कि यहां से निकला संदेश किसी के विरोध में नहीं, साझा हित में हो। भारत के पास सभी सदस्यों को करीब लाने और मौजूदा संकट का समाधान पेश करने का मौका है।

पांचवां, ग्लोबल साउथ की राजनीतिक आवाजः बैठक में यह स्पष्ट हुआ किब्रिक्स स्वयं को केवल आर्थिक समूह नहीं, बल्कि विकासशील देशों की सामूहिक राजनीतिक आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों की समस्याओं—जैसे खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और कर्ज—को वैश्विक एजेंडा में प्रमुखता देने की बात कही गई।

छठा, संयुक्त राष्ट्र सुधार की मांगः भारत और ब्राजील ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता दोहराई। यह संदेश था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी संस्थाओं में अब नई वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होना चाहिए।

सातवां, ब्रिक्स के भीतर मतभेद भी सामने आएः हालांकि बैठक में एकजुटता दिखाई गई, लेकिन यह भी स्पष्ट हुआ कि सभी सदस्य अमेरिका-विरोधी नीति पर पूरी तरह एकमत नहीं हैं। भारत और ब्राजील जैसे देश पश्चिम के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना चाहते हैं, जबकि रूस और ईरान अधिक आक्रामक रुख चाहते हैं। इससे यह संकेत मिला कि ब्रिक्स अभी पूर्ण राजनीतिक गठबंधन नहीं, बल्कि साझा हितों वाला मंच है। समग्र रूप से कहा जाए तो, इस बैठक का वैश्विक संदेश यह था कि उभरती शक्तियाँ अब विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में अधिक स्वतंत्र, संतुलित और पश्चिम से अलग भूमिका चाहती हैं। ब्रिक्स ने यह दिखाने की कोशिश की कि "ग्लोबल साउथ" अब केवल दर्शक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन का सक्रिय खिलाड़ी बनना चाहता है। चूंकि ब्रिक्स अब केवल उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह नहीं रहा, इसकी भूमिका आज कहीं ज्यादा व्यापक हो चुकी है।

वास्तव में यह वैश्विक संतुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत का रोल इसमें सबसे अहम हो जाता है। उसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं, जबकि रूस, ईरान और चीन के साथ भी बैलेंस रखा है। उसने हमेशा संवाद से समाधान की बात की है। यह रवैया उसे भरोसेमंद साथी बनाता है।

प्रेरणा

दर्द से ऊपर था देशप्रेम : अमर शहीद सुखदेव का अद्भुत साहस

भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक संघर्ष का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उन असंख्य वीरों के त्याग, तपस्या और असाधारण साहस का फल थी जिन्होंने अपने प्राणों को भी राष्ट्र के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों में सुखदेव थापर का नाम अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ लिया जाता है। वे केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि दृढ़ इच्छाशक्ति, असाधारण सहनशक्ति और अटूट देशभक्ति के प्रतीक थे। उनके जीवन की अनेक घटनाएं आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनमें से एक घटना आगरा की है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि जब मन में देशप्रेम की ज्वाला जलती है, तब शरीर का सबसे बड़ा दर्द भी छोटा पड़ जाता है।

सुखदेव बचपन से ही साहसी और जिद्दी स्वभाव के थे। यदि वे किसी बात को सही मान लेते, तो फिर उसे पूरा करके ही मानते थे। उनके साथी भी जानते थे कि सुखदेव अपने निर्णयों से पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। क्रांतिकारी जीवन में यह गुण उनके लिए शक्ति बन गया था। अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करते समय हर पल गिरफ्तारी, यातना और मृत्यु का भय बना रहता था, लेकिन सुखदेव इन सबसे ऊपर उठ चुके थे। उनके लिए व्यक्तिगत सुख-दुख का कोई महत्व नहीं था। उनका पूरा जीवन केवल मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पित था।

विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपने बाएं हाथ पर 'ओउम' और अपना नाम गुदवा लिया था। उस समय यह केवल एक धार्मिक और व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतीक था, लेकिन जब वे क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और अंग्रेज सरकार की नजरों में आए, तब वही निशान उनकी पहचान बन गया। फरारी के दिनों में किसी भी छोटी पहचान के कारण अंग्रेज पुलिस उन्हें पकड़ सकती थी। ऐसे समय में उन्होंने अपने हाथ पर बने उस निशान को मिटाने का निश्चय किया। लेकिन उन्होंने यह काम किसी सामान्य तरीके से नहीं किया, बल्कि अपनी सहनशक्ति की परीक्षा के रूप में किया।

उस समय आगरा में क्रांतिकारी दल बम निर्माण की तैयारी कर रहा था। बम बनाने के लिए वहां नाइट्रिक एसिड रखा गया था। यह अत्यंत खतरनाक रसायन होता है जो त्वचा को बुरी तरह जला देता है। एक दिन सुखदेव ने बिना किसी साथी को बताए अपने हाथ पर बने 'ओउम' और नाम पर वही एसिड डाल दिया। यह केवल पहचान मिटाने का प्रयास नहीं था, बल्कि वह जानना चाहते थे कि शरीर कितनी पीड़ा सह सकता है। उन्होंने स्वयं को दर्द की अग्नि में झोंक दिया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था।

धीरे-धीरे एसिड ने अपना असर दिखाना शुरू किया। हाथ की त्वचा बुरी तरह जल गई। वहां गहरे घाव बन गए और पूरा हाथ सूज गया। दर्द इतना भयानक था कि सामान्य व्यक्ति शायद चीख उठता, लेकिन सुखदेव ने अपने होंठों से एक शब्द तक नहीं निकाला। शाम तक उन्हें तेज बुखार भी हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी पीड़ा का किसी से जिक्र नहीं किया। वे उसी प्रकार अपने साथियों के बीच सामान्य बने रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह केवल शारीरिक सहनशक्ति नहीं थी, बल्कि मानसिक दृढ़ता की चरम सीमा थी।

तीन दिन तक उन्होंने इस भयानक दर्द को अकेले सहा। जब वे नहाने के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपनी कमीज उतारी, तब उनके साथी भगत सिंह और चन्द्रशेखर आजाद की नजर उनके हाथ पर पड़ी। हाथ पर गहरे घाव थे, त्वचा जल चुकी थी और सूजन साफ दिखाई दे रही थी। यह देखकर दोनों क्रांतिकारी स्तब्ध रह गए। उन्हें बहुत क्रोध आया कि सुखदेव ने इतनी बड़ी पीड़ा छिपाकर रखी और किसी को बताया तक नहीं। वे जानते थे कि यह चोट कितनी गंभीर है और यदि सही उपचार न किया जाए तो स्थिति और खराब हो सकती है।

लेकिन सुखदेव का उत्तर सुनकर सभी साथी चुप हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "शिनाख्त भी मिट जाएगी और एसिड में कितनी जलन होती है, इसका भी पता चल जाएगा।" यह वाक्य उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। उनके लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता था। वे हर कष्ट को देशभक्ति की साधना मानते थे। जिस सहजता और हंसी के साथ उन्होंने इतनी भयानक पीड़ा को स्वीकार किया, वह असाधारण था। यह केवल एक क्रांतिकारी का साहस नहीं था, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा थी।

घटना के बाद भी उन्होंने आराम नहीं किया। उनके साथियों ने उनसे दवा लगाने, मलहम कराने और पट्टी करवाने की बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। वे उसी घायल अवस्था में लगातार पार्टी का काम करते रहे। उनके लिए देश का मिशन किसी भी व्यक्तिगत पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण था। वे जानते थे कि स्वतंत्रता की राह आसान नहीं है। उसमें यातनाएं, कठिनाइयां और बलिदान हर कदम पर मिलते हैं। शायद यही कारण था कि वे अपने शरीर और मन दोनों को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखना चाहते थे।

चार-पांच दिन तक वे आगरा में उसी हालत में रहे। घाव गहरे थे, बुखार भी बना हुआ था, लेकिन उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। इसके बाद वे अगले मिशन के लिए लाहौर चले गए। यह घटना यह बताती है कि सुखदेव केवल विचारों के क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे अपने जीवन में उन विचारों को पूरी तरह जीते थे। उनका प्रत्येक कार्य यह साबित करता था कि देश के लिए समर्पण केवल शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और साहस से सिद्ध होता है।

आज के समय में जब छोटी-छोटी परेशानियों से लोग टूट जाते हैं, तब सुखदेव का जीवन हमें मानसिक शक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यदि उद्देश्य महान हो, तो कठिन से कठिन पीड़ा भी इंसान को रोक नहीं सकती। उनका जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत है। भारत की आजादी ऐसे ही वीरों की तपस्या और बलिदान का परिणाम है जिन्होंने अपने सुख, आराम और जीवन तक को देश के लिए न्योछावर कर दिया। सुखदेव थापर का यह साहसिक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा देशप्रेम केवल नारों और शब्दों में नहीं होता, बल्कि वह त्याग, सहनशीलता और अटूट आत्मबल में दिखाई देता है। उनका जीवन हर भारतीय को यह प्रेरणा देता है कि कठिनाइयों से डरकर पीछे हटना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा रखता है, वही इतिहास में अमर होता है। सुखदेव ने अपने अद्भुत साहस और सहनशक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि क्रांतिकारी केवल हथियारों से नहीं, बल्कि अपने आत्मबल से भी साम्राज्यों की नींव हिला देते हैं।

सारे Jewellers ले आये नई स्कीम, अब पुराना Gold बेचो नहीं, बदलो! मिलेगा पूरा फायदा

हाल ही में सोने के आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से सोने की खरीद कुछ समय के लिए टालने की अपील के बाद देश की प्रमुख आभूषण कंपनियां अब सोना पुनर्चक्रण योजनाओं यानि गोल्ड रि-साइक्लिंग स्कीम्स को तेजी से बढ़ावा दे रही हैं। इस पहल का उद्देश्य एक ओर घरेलू बाजार में सोने की मांग को संतुलित करना है, वहीं दूसरी ओर सोने के आयात पर निर्भरता कम कर देश को सीमा शुल्क भुगतान में राहत दिलाना भी है। देश की जानी मानी कंपनियां जैसे Kalyan Jewellers, Malabar Gold & Diamonds, Muthoot Exim, MMTC-PAMP और Tanishq पुरानी ज्वेलरी, टूटे हुए आभूषण, पुराने डिजाइन के गहने और सोने के सिक्कों को नए गहनों के बदले स्वीकार कर रही हैं। इन कंपनियों का दावा है कि इससे नया कारोबार भी बढ़ेगा और सोने के आयात का दबाव भी घटेगा।

मुथूट एक्जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीयूर शाह के अनुसार सोना पुनर्चक्रण का मतलब ग्राहकों से पुराना सोना खरीदकर उसे शुद्ध करना और फिर दोबारा उद्योग में उपयोग के लिए उपलब्ध कराना है। उनका कहना है कि यदि भारतीय घरों में मौजूद कुल सोने का केवल एक प्रतिशत भी पुनर्चक्रित हो जाए तो देश का सोना आयात लगभग तीन सौ टन तक कम हो सकता है। यह भारत के कुल वार्षिक सोना आयात का लगभग चालीस प्रतिशत है।

हम आपको बता दें कि कंपनियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग योजनाएं शुरू की हैं। कल्याण ज्वेलर्स ने 'नेशन फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया' पहल के तहत पुराना सोना विनिमय योजना शुरू की है। इसके तहत ग्राहक अपने पुराने या अनुपयोगी गहनों को नए डिजाइन में बदलवा सकते हैं। वहीं मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपनी स्वर्ण मौद्रीकरण योजना में न्यूनतम जमा सीमा दस ग्राम से घटाकर केवल एक ग्राम कर दी है। कंपनी ग्राहकों को सोने के वजन या नकद दोनों रूपों में भुगतान का विकल्प दे रही है।

मुथूट एक्जिम के देशभर में सौ केंद्र हैं और कंपनी के अनुसार उसने अब तक करीब पांच टन पुराना सोना खरीदा है। चालू वित्त वर्ष में ही लगभग एक हजार किलोग्राम सोना पुनर्चक्रण के लिए जुटाया गया है। दूसरी ओर तनिष्क की 'ओल्ड गोल्ड न्यू इंडिया' मुहिम के अंतर्गत नौ कैरेट से बाइस कैरेट तक के सोने को स्वीकार किया जा रहा है। कंपनी किसी भी ज्वेलर का सोना लेने का दावा करती है, चाहे वह टूटा हुआ या छोटा आभूषण ही क्यों न हो।

देखा जाये तो ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि पुराने गहनों का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। कंपनियों का कहना है कि अब पारंपरिक अंदाजे की बजाय वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स के अनुसार सोने की शुद्धता जांचने के लिए कैरेट मीटर और सटीक वजन मशीनों का उपयोग किया जाता है। मुथूट एक्जिम ने बताया कि वह एक्स आर एफ तकनीक वाली मशीनों का प्रयोग करता है, जिससे केवल तीस सेकंड में यह पता चल जाता है कि गहनों में सोने, चांदी, तांबा, जस्ता या निकल की कितनी मात्रा है। वहीं एमएमटीसी पैंप ने कहा कि उसकी प्रक्रिया में जर्मन तकनीक आधारित आधुनिक मशीनों का उपयोग होता है, जिससे ग्राहकों के गहनों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता।

हम आपको बता दें कि पुराने सोने के बदले मिलने वाली राशि बाजार भाव और शुद्धता पर निर्भर करती है। मुथूट एक्जिम प्रतिदिन भारतीय बुलियन और ज्वेलर्स एसोसिएशन के बाजार भाव के अनुसार मूल्य तय करता है। कुछ कंपनियां सेवा शुल्क भी वसूलती हैं। मुथूट एक्जिम सोने की कीमत का लगभग तीन प्रतिशत सेवा शुल्क लेता है, जबकि एमएमटीसी पैंप वस्तु एवं सेवा कर के साथ अन्य शुल्क भी लागू करता है। कल्याण ज्वेलर्स का कहना है कि पुराने सोने के विनिमय पर कर नहीं लगता, केवल नए गहनों की खरीद पर कर देय होता है। कंपनी ने दावा किया है कि दस ग्राम सोने पर ग्राहकों को लगभग पूरा मूल्य दिया जाता है और केवल मिश्रित धातु अलग करने का मामूली शुल्क लिया जाता है।

इसी बीच आभूषण उद्योग का विस्तार अब शॉपिंग मॉल संस्कृति को भी प्रभावित कर रहा है। नई दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों में ज्वेलरी स्टोर अब बड़े मॉलों के प्रमुख आकर्षण बनते जा रहे हैं। चार वर्ष पहले जहां मॉल क्षेत्रफल का केवल एक प्रतिशत हिस्सा आभूषण दुकानों के पास था, वहीं अब यह बढ़कर लगभग दस प्रतिशत तक पहुंच गया है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनियों के अनुसार संगठित खुदरा बाजार में आभूषण क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2019 के दो प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में आठ प्रतिशत तक पहुंच गई है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में बड़े आकार के ज्वेलरी शोरूम तेजी से खुल रहे हैं। उपभोक्ताओं का भरोसा संगठित और प्रतिष्ठित ब्रांडों की ओर बढ़ने से यह क्षेत्र मॉल संचालकों के लिए प्रमुख किरायेदार बन गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आभूषण खरीद अभी भी भरोसे और अनुभव पर आधारित है। लोग परिवार के साथ दुकान जाकर डिजाइन देखना और समझकर खरीदारी करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र ऑनलाइन बिक्री से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। तनिष्क, मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, कल्याण ज्वेलर्स और कैरटलैन जैसे ब्रांड अब महानगरों के साथ छोटे शहरों में भी मॉलों के लिए भीड़ आकर्षित करने वाले प्रमुख केंद्र बन चुके हैं।

अभियान

जहां एक साथ बरसती है भोलेनाथ और आदिशक्ति की कृपा, अद्भुत है बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा

भारत की पवित्र धरती पर भगवान शिव के अनगिनत मंदिर स्थित हैं, जहां हर दिन करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के दीप जलाते हैं। कोई दुखों से मुक्ति पाने के लिए महादेव की शरण में आता है, तो कोई अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भोलेनाथ का अभिषेक करता है। शिव वह देव हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। लेकिन भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों का महत्व इन सभी शिवालयों से अलग और अत्यंत दिव्य माना गया है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से जीवन के दुख दूर होते हैं और आत्मा को अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। इन्हीं पवित्र ज्योतिर्लिंगों में एक है बाबा बैद्यनाथ धाम, जिसकी महिमा पूरे विश्व में अद्वितीय मानी जाती है।

यह केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, बल्कि वह पावन स्थान है जहां भगवान शिव के साथ मां शक्ति भी विराजमान हैं। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम को विश्व का इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है जहां शिव और शक्ति एक साथ भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। झारखंड के देवघर में स्थित यह दिव्य धाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। यहां पहुंचते ही भक्तों को ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं कैलाश की दिव्यता धरती पर उतर आई हो।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उस समय सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक भाग किए। जहां-जहां माता सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। माना जाता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में माता सती का हृदय गिरा था। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में भी पूजित है।

जब शिव और शक्ति दोनों एक ही स्थान पर विराजमान हों, तब उस धाम की महिमा कितनी महान होगी, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। यही कारण है कि यहां आने वाला हर भक्त स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता है। यहां केवल भगवान शिव की ही नहीं, बल्कि मां पार्वती की भी विशेष पूजा होती है। भक्त मानते हैं कि जहां शिव हैं, वहां शक्ति अवश्य हैं और जहां शक्ति हैं, वहां सृष्टि का संपूर्ण कल्याण संभव है। बाबा बैद्यनाथ धाम इसी दिव्य सत्य का जीवंत प्रतीक है।

यहां का वातावरण हर क्षण "बोल बम" और "हर हर महादेव" के जयघोष से गूंजता रहता है। श्रावण मास में तो यह धाम भक्तिभाव के महासागर में परिवर्तित हो जाता है। देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। कांवरिए सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर पैदल यात्रा करते हुए बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पित करते हैं। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं होती, बल्कि आत्मा की यात्रा होती है। भक्त अपने कष्ट, दुख और चिंताओं को भूलकर केवल भोलेनाथ के नाम में लीन हो जाते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से यहां जलाभिषेक करने वाले भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी कारण बाबा बैद्यनाथ को "कामना ज्योतिर्लिंग" भी कहा जाता है। यहां आने वाला हर भक्त अपनी कोई न कोई इच्छा लेकर आता है। कोई संतान सुख मांगता है, कोई स्वास्थ्य, कोई सुख-समृद्धि और कोई मानसिक शांति। लेकिन कहा जाता है कि बाबा बैद्यनाथ के दरबार से कोई भी भक्त खाली हाथ वापस नहीं लौटता। महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और मां शक्ति अपनी ममता से भक्तों के जीवन को सुख और शांति से भर देती हैं।

बाबा बैद्यनाथ धाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां शिव और शक्ति का अद्भुत संतुलन देखने को मिलता है। भगवान शिव को चेतना और शक्ति को ऊर्जा का स्वरूप माना गया है। शिव बिना शक्ति के शून्य हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। यही कारण है कि सनातन धर्म में शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बाबा बैद्यनाथ धाम इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है।

जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है और बाबा बैद्यनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, तब उसका मन स्वतः ही भक्ति में डूब जाता है। घंटियों की ध्वनि, मंत्रों का उच्चारण और वातावरण में फैली आध्यात्मिक ऊर्जा मन को भीतर तक स्पर्श करती है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं महादेव अपने भक्तों को अपने सान्निध्य का अनुभव करा रहे हों। वहीं मां पार्वती के दर्शन से भक्तों के हृदय में मातृत्व और करुणा का भाव जागृत होता है। यह धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और ईश्वर से मिलन का द्वार है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहां शिव और शक्ति की संयुक्त पूजा करता है, उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि बाबा नगरी की महिमा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहां केवल भारत से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। सभी भक्त एक ही भाव लेकर आते हैं—भोलेनाथ और मां शक्ति की कृपा प्राप्त करने का भाव।

भक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप समर्पण होता है और बाबा बैद्यनाथ धाम यही समर्पण सिखाता है। यहां आकर व्यक्ति अपने अहंकार को भूल जाता है। वह केवल शिव का दास बन जाता है। महादेव की भक्ति मनुष्य को भीतर से बदल देती है। जो व्यक्ति जीवन में दुख, तनाव और निराशा से घिरा होता है, उसे यहां आकर नई ऊर्जा और नई आशा मिलती है। यही कारण है कि बाबा बैद्यनाथ धाम को केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवंत आस्था का केंद्र माना जाता है।

सनातन धर्म में शिव को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन वे केवल विनाश नहीं करते, बल्कि जीवन को नया स्वरूप भी देते हैं। वहीं मां शक्ति सृष्टि की आधारशिला हैं। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ होती हैं, तब भक्तों के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलता है। बाबा बैद्यनाथ धाम इसी दिव्य मिलन का प्रतीक है। यहां हर पत्थर, हर घंटी और हर मंत्र में शिव और शक्ति की ऊर्जा महसूस होती है।

आज के आधुनिक समय में जहां मनुष्य भौतिक सुखों की दौड़ में मानसिक शांति खोता जा रहा है, वहां ऐसे पवित्र धाम लोगों को अध्यात्म की ओर लौटने की प्रेरणा देते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का भी स्थान है। यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव करता है। उसे यह एहसास होता है कि ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं है।

बाबा बैद्यनाथ धाम की महिमा शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती। यह वह धाम है जहां शिव अपने भक्तों को अपनापन देते हैं और मां शक्ति अपनी ममता का आशीर्वाद बरसाती हैं। यहां आने वाला हर भक्त अपने जीवन में अद्भुत शांति और आनंद का अनुभव करता है। शायद यही कारण है कि सदियों से यह धाम करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

जब भक्त बाबा बैद्यनाथ के चरणों में सिर झुकाता है, तब उसके मन से भय, चिंता और दुख दूर हो जाते हैं। उसे विश्वास हो जाता है कि अब उसके जीवन की नैया स्वयं भोलेनाथ और मां शक्ति संभालेंगे। यही विश्वास, यही श्रद्धा और यही भक्ति बाबा बैद्यनाथ धाम को विश्व का सबसे अद्भुत और दिव्य ज्योतिर्लिंग बनाती है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

शहरी निकाय चुनाव: अंतिम दिन कांग्रेस-भाजपा ने झोंकी ताकत, मतदान कल, कांगड़ा में 218 प्रत्याशी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को प्रचार का अंतिम दिन रहा और दोपहर तीन बजे के बाद चुनावी शोर पूरी तरह थम गया। अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर सहित दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज नेताओं ने पूरे दिन जनसभाओं, रोड शो और डोर-टू-डोर कैंपेन के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश की। अब सभी की निगाहें शनिवार को होने वाले मतदान और 31 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीतिक दिशा का अहम संकेत माने जा रहे हैं।

प्रदेश के चार नगर निगम—सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला—इस बार चुनावी मुकाबले का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। इन चारों नगर निगमों के चुनावों को केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़े राजनीतिक परीक्षण के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई बना लिया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन माहौल बेहद गर्म रहा और हर इलाके में नेताओं की सक्रियता चरम पर दिखाई दी।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन के गंज बाजार में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है और शहरी निकायों को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और कई मंत्रियों ने भी अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बूथ स्तर तक पहुंचकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और अंतिम दिन अधिक से अधिक मतदाताओं तक

पहुंचने की रणनीति अपनाई।

दूसरी ओर, भाजपा ने भी अंतिम दिन पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभाला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई स्थानों पर रैलियां कीं और सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कांग्रेस सरकार की नीतियों से असंतुष्ट है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा को व्यापक जनसमर्थन मिलेगा। सांसद अनुराग ठाकुर ने कांगड़ा और हमीरपुर क्षेत्रों में जनसभाएं कीं और भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने भी विभिन्न इलाकों में जाकर प्रचार अभियान को गति दी। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि प्रदेश में विकास कार्यों की धीमी गति और प्रशासनिक असंतोष का असर चुनाव परिणामों में दिखेगा।

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार शुक्रवार दोपहर तीन बजे के बाद सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रचार, रैली, जुलूस और लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी गई। इसके बाद उम्मीदवारों को केवल घर-घर जाकर व्यक्तिगत संपर्क अभियान चलाने की अनुमति दी गई। साथ ही मतदान से पहले राज्य में ड्राई-डे भी लागू कर दिया गया है, जिसके तहत शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

इस बार शहरी निकाय चुनाव में कुल 439 पदों के लिए 1147 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांगड़ा जिला सबसे अधिक प्रत्याशियों वाला क्षेत्र बनकर उभरा है, जहां 218 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा मंडी में 180, शिमला में 123, सोलन में 121, ऊना में 118, कुल्लू में 100, बिलासपुर में 87, सिरमौर में 84, चंबा में 72 और हमीरपुर में 44 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में शामिल हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा और बहुकोणीय है, जहां हर सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।

चार नगर निगमों में हो रहे ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहां का परिणाम राज्य की राजनीतिक हवा का संकेत देगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव केवल स्थानीय मुद्दों पर आधारित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य और राष्ट्रीय राजनीति की छाया भी साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल इस चुनाव को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए प्रचार अभियान में बड़े नेताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। शहरी निकाय चुनावों में इस बार युवाओं, महिलाओं और शहरी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। रोजगार, विकास, सड़क, पानी और स्वच्छता जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा के केंद्र में रहे हैं। दोनों दलों ने अपने-अपने स्तर पर इन मुद्दों को जनता के बीच प्रमुखता से उठाया है।

अब जबकि प्रचार थम चुका है, प्रशासन और चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। मतदाता शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 31 मई को यह साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया है।

ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के बीच पटना में गोलीबारी मसाला कारोबारी की हत्या से सनसनी

पटना। राजधानी पटना में गुरुवार देर रात उस समय दहशत और सनसनी फैल गई जब सिविल डिफेंस की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान अपराधियों ने एक मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर में सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए चल रहे इस अभ्यास के बीच हुई यह वारदात न सिर्फ कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे अंधेरे और आपातकालीन स्थितियों का फायदा उठाकर अपराधी अपनी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।

घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लेपुर हाट सब्जी मंडी की है, जो आम दिनों में सुबह से लेकर रात तक चहल-पहल वाला इलाका माना जाता है। लेकिन ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के चलते जब पूरे इलाके की लाइटें बंद थीं और चारों ओर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, तभी अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लोगों को कुछ समझ आता उससे पहले ही अपराधियों ने एक व्यापारी को निशाना बनाकर बेहद नजदीक से गोली मार दी और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए।

मृतक की पहचान टिकिया टोली निवासी 35 वर्षीय पिंटू कुमार के रूप में हुई है, जो अपने पिता नेपाली साव के पुत्र थे और मुसल्लेपुर हाट में मसालों का कारोबार करते थे। बताया जाता है कि पिंटू कुमार लंबे समय से इस बाजार में सक्रिय थे और उनका कारोबार स्थानीय स्तर पर काफी स्थापित था। उनकी अचानक और हिंसक मौत से न सिर्फ उनका परिवार सदमे में है, बल्कि पूरे व्यापारिक समुदाय में भय और आक्रोश का माहौल है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को प्रतिक्रिया देने का भी मौका नहीं मिला। अंधेरे का लाभ उठाकर आए हमलावर पहले से ही इलाके की रेकी कर चुके थे या फिर किसी खास योजना के तहत मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने पिंटू कुमार को निशाना बनाया, एक के बाद एक गोली चलाई गई और फिर तुरंत ही वे अंधेरे में गायब हो गए। ब्लैकआउट की वजह से आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की विजिबिलिटी भी प्रभावित हुई, जिससे शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग

घायल पिंटू कुमार को उठाकर नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस खबर के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने भी इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और भयावह बताया है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। सिटी पुलिस अधीक्षक (पटना पूर्वी) परिचय कुमार और पटना सिटी के अपर पुलिस अधीक्षक राजकिशोर सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस अधिकारियों ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी और किसी भी तरह के साक्ष्य को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से कई अहम सबूत एकत्र किए हैं। इनमें गोलियों के खोखे, खून के नमूने और अन्य भौतिक साक्ष्य शामिल हैं। इन सभी को जांच के लिए भेजा गया है ताकि वारदात में इस्तेमाल हथियार और हमलावरों की पहचान की जा सके। पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक जांच से मामले को सुलझाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।

पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। हालांकि ब्लैकआउट के कारण कई कैमरों में स्पष्ट दृश्य नहीं मिल पा रहा है, फिर भी तकनीकी टीम डाटा रिकवर करने और अन्य स्रोतों से सुराग जुटाने में लगी है। पुलिस को आशंका है कि हमलावर स्थानीय हो सकते हैं या फिर पहले से इलाके से परिचित रहे होंगे।

सिटी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि यह घटना ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान हुई, जब सुरक्षा अभ्यास के तहत पूरे इलाके की लाइटें बंद कर दी गई थीं। इसी का फायदा उठाकर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इस घटना के बाद इलाके में व्यापारियों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बाजार क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस गश्त नहीं रहती, जिसके कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने मांग की है कि इलाके में स्थायी पुलिस चौकी और रात्रि गश्त को मजबूत किया जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल जैसी स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत होनी चाहिए थी, ताकि आपातकालीन अभ्यास के दौरान किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या इस तरह के अभ्यास के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती पर्याप्त थी या नहीं। परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। परिवार का कहना है कि पिंटू कुमार किसी विवाद में नहीं थे और उनकी हत्या एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विभिन्न एंगल से जांच शुरू कर दी है। आपसी रंजिश, व्यापारिक विवाद और स्थानीय स्तर पर किसी पुराने झगड़े की भी जांच की जा रही है।

आयकर विभाग ने जारी किए ITR-1 और ITR-4 फॉर्म, देश में रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया शुरू, करदाताओं के लिए नए बदलाव और डिजिटल टैक्स सिस्टम में बड़ा कदम

नई दिल्ली में आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-26 और आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ITR-1 और ITR-4 के एक्सेल यूटिलिटी फॉर्म जारी कर दिए हैं, जिसके साथ ही देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर साल की तरह इस बार भी लाखों वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे कारोबारी, फ्रीलांसर और पेशेवर वर्ग इस प्रक्रिया से सीधे जुड़े हैं और अब वे अपने वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का हिसाब आयकर विभाग को प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

आयकर विभाग ने इस बार रिटर्न प्रक्रिया को पहले से अधिक डिजिटल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाने पर जोर दिया है। विभाग ने अपने आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर दोनों फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं, जहां से करदाता इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक विवरण भरकर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता बिना किसी तकनीकी कठिनाई के समय पर और सही तरीके से अपनी आय की जानकारी जमा कर सकें।

इस बार फॉर्म जारी होने के साथ ही टैक्स विशेषज्ञों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी करदाताओं को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि समय से पहले तैयारी करने से अंतिम समय में होने वाली त्रुटियों और सर्वर भीड़ जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग और छोटे व्यापारियों को अपने सभी दस्तावेज जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रमाण पत्र और अन्य आय स्रोतों से जुड़े रिकॉर्ड पहले से तैयार रखने की सलाह दी जा रही है।

आयकर विभाग के अनुसार इस बार ITR फॉर्म में कुछ तकनीकी और संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य टैक्स फाइलिंग को और अधिक सरल और सटीक बनाना है। डिजिटल सिस्टम में सुधार करते हुए कई जगहों पर ऑटो-वैलिडेशन और प्री-फिल्ड डेटा की सुविधा को मजबूत किया गया है, जिससे करदाता को बार-बार एक ही जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गलतियों की संभावना भी कम होगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि वेतनभोगी करदाता और छोटे व्यवसायी 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वहीं, बजट 2026-27 में किए गए नए प्रावधानों के अनुसार बिना ऑडिट वाले छोटे कारोबारी और फ्रीलांसरों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। यह अतिरिक्त समय उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अपने व्यवसायिक रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में थोड़ा अधिक समय लेते हैं।

चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित रंजन ने बताया कि इस बार जारी किए गए फॉर्म पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित और डेटा-केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने यूटिलिटी सिस्टम को अपग्रेड किया है, जिससे अब फॉर्म लाइव होते ही करदाता तुरंत फाइलिंग प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। उनके अनुसार, यह बदलाव टैक्स सिस्टम को तेज और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आईटीआर-1 फॉर्म, जिसे सामान्य भाषा में 'सहज' कहा जाता है, मुख्य रूप से उन करदाताओं के लिए होता है जिनकी आय सीमित स्रोतों से आती है। इसमें वेतन, एक मकान से किराया आय और ब्याज जैसी आम आय शामिल होती है। यह फॉर्म सरल और कम जटिल होता है, जिससे सामान्य नौकरीपेशा व्यक्ति इसे आसानी से भर सकते हैं।

दूसरी ओर, आईटीआर-4 फॉर्म उन छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और पेशेवरों के लिए होता है जो प्रीसम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में करदाता को अनुमानित आय के आधार पर टैक्स देना होता है, जिससे उन्हें विस्तृत लेखा-जोखा रखने की आवश्यकता कम हो जाती है। यह फॉर्म विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका व्यवसाय छोटा या मध्यम स्तर का होता है और जिनकी आय एक निश्चित सीमा के भीतर रहती है।

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि देश में वर्तमान में कुल सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म लागू हैं, जो करदाता की आय के प्रकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित हैं। इसमें ITR-1 से लेकर ITR-7 तक शामिल हैं। प्रत्येक फॉर्म का उद्देश्य अलग-अलग प्रकार के करदाताओं को उनके अनुसार सरल और व्यवस्थित टैक्स फाइलिंग सुविधा प्रदान करना है।

डिजिटल इंडिया अभियान के बाद से टैक्स सिस्टम में तेजी से बदलाव देखा गया है। अब अधिकतर प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, जिससे करदाताओं को आयकर कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ई-फाइलिंग सिस्टम ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ाई है। करदाता अब अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस डिजिटल बदलाव के कारण कर अनुपालन में भी सुधार हुआ है।

राजस्थान युवा संघ का सूरत में भव्य आयोजन, स्व. विक्रम सिंह शेखावत के सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया

सूरत में सामाजिक एकता, सेवा और संगठन की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थान युवा संघ ने एक बार फिर स्व. विक्रम सिंह शेखावत के विचारों और सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। यह आयोजन केवल एक औपचारिक स्वागत समारोह नहीं रहा, बल्कि इसमें समाज, संस्कृति और युवा शक्ति की भूमिका को लेकर गहन चर्चा और विचार-विमर्श भी देखने को मिला।

इस कार्यक्रम में राजकुमार रिणवा और अभिनव महर्षि का राजस्थान युवा संघ कार्यालय में आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजबंधु, युवा कार्यकर्ता और संगठन से जुड़े लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अतिथियों का पारंपरिक "अतिथि देवो भवः" की भावना के साथ स्वागत किया।

कार्यक्रम का वातावरण पूरी तरह सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था, जहां संगठन की गतिविधियों के साथ-साथ समाज में एकता और सहयोग की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि आज के समय में युवाओं की भूमिका केवल रोजगार या व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज निर्माण में भी उनकी सक्रिय भागीदारी जरूरी है।

इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनव महर्षि ने राजस्थान युवा संघ की कार्यकारिणी की सराहना करते हुए कहा कि संगठन जिस तरह स्व. विक्रम सिंह शेखावत के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, वह सराहनीय है। उन्होंने कहा कि युवाओं में ऊर्जा और क्षमता है, जिसे सही दिशा दी जाए तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। उनके अनुसार, ऐसे संगठन न केवल सामाजिक एकता

को मजबूत करते हैं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को भी जीवित रखते हैं।

राजकुमार रिणवा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान युवा संघ के सदस्य भले ही अपने प्रदेश से दूर रहते हों, लेकिन वे अपनी मातृभूमि की संस्कृति, परंपरा और अपनत्व की भावना को निरंतर जीवित रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह संगठन एक पुल की तरह काम कर रहा है, जो दूर बसे लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। उन्होंने इस प्रयास को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा मिलती है।

कार्यक्रम के दौरान जगदीश शर्मा ने संगठन की विभिन्न गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान युवा संघ द्वारा समय-समय पर मानव सेवा, गौ सेवा और सामाजिक सहयोग से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य केवल सेवा करना नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना है।

संघ के प्रतिनिधि रामावतार पारीक ने बताया कि संगठन स्व. विक्रम सिंह शेखावत के सपनों को साकार करने के लिए लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का मूल उद्देश्य सामाजिक एकता को मजबूत करना, युवाओं को जोड़ना और सेवा कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक संदेश देना है।

कार्यक्रम में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए और संगठन की गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब समाज कई चुनौतियों से गुजर रहा है, ऐसे में युवाओं का संगठित होकर समाजहित में काम करना अत्यंत आवश्यक है।

इस अवसर पर कई प्रमुख कार्यकर्ता जैसे सज्जन महर्षि, ओमप्रकाश शेखावाटी, संजय जैन, राजेंद्र चौधरी, विनोद सारस्वत, महेंद्र पटेल, कपिल सोनी, हरिओम स्वामी, विनोद प्रजापति, रोहित मेवाड़ा, मुकेश प्रजापति, श्याम माली, गंगाधर डूड़ी, प्रमोद शर्मा और राधेश्याम शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

पूरे कार्यक्रम में उत्साह, सामाजिक जुड़ाव और सांस्कृतिक भावना का माहौल देखने को मिला। अंत में सभी उपस्थित लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाते हुए समाज सेवा, एकता और संस्कृति संरक्षण के कार्यों में निरंतर योगदान देते रहेंगे।

सोना वायदा में 2881 रुपये और चांदी वायदा में 17152 रुपये की भारी गिरावट: क्रूड ऑयल वायदा 256 रुपये तेज

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 259238.92 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 50701.73 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 208537.2 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 3286.87 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 36845.59 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सत्र के आरंभ में 160790 रुपये के भाव पर खूलकर, 160992 रुपये के दिन के उच्च और 158537 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 161978 रुपये के पिछले बंद के सामने 2881 रुपये या 1.78 फीसदी की गिरावट के साथ 159097 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा था। गोल्ड-गिनी मई वायदा 2056 रुपये या 1.58 फीसदी औंधकर 127829 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल मई वायदा 266 रुपये या 1.64 फीसदी औंधकर 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी जून वायदा 160003 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160349 रुपये और नीचे में 158037 रुपये पर पहुंचकर, 2824 रुपये या 1.75 फीसदी औंधकर 158629 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम 159962 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 160620 रुपये और नीचे में 158300 रुपये पर पहुंचकर, 161664 रुपये के पिछले बंद के सामने 2821 रुपये या 1.74 फीसदी औंधकर 158843 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा 280000 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 283219 रुपये और नीचे में 270380 रुपये पर पहुंचकर, 291102 रुपये के पिछले बंद के सामने 17152 रुपये या 5.89 फीसदी गिरकर 273950 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा 16636 रुपये या 5.67 फीसदी गिरकर 276845 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो

कमोडिटी वायदाओं में 50701.73 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 208537.2 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 36845.59 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

जून वायदा 16779 रुपये या 5.72 फीसदी की गिरावट के साथ 276704 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 7083.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा 38.65 रुपये या 2.79 फीसदी घटकर 1346.8 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि जस्ता मई वायदा 3.9 रुपये या 1.06 फीसदी औंधकर 363.5 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 5.95 रुपये या 1.54 फीसदी औंधकर 379.55 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मई वायदा 1.35 रुपये या 0.66 फीसदी औंधकर 202.25 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 6732.79 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 9811 रुपये के भाव पर खूलकर, 10112 रुपये के दिन के उच्च और 9807 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 256 रुपये या 2.63 फीसदी की बढ़त के साथ 9980 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी मई वायदा 258 रुपये या 2.65 फीसदी की मजबूती के साथ 9983 रुपये प्रति बैरल बोला गया। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सत्र के आरंभ में 281 रुपये के भाव पर खूलकर, 283.8 रुपये के दिन के उच्च और 278.5 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.4 रुपये के पिछले बंद के सामने 2.7 रुपये या 0.97 फीसदी की मजबूती के साथ 280.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा 2.8 रुपये या 1.01 फीसदी की मजबूती के साथ 280.2 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बोला गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सत्र के आरंभ में 994.5 रुपये के भाव पर खूलकर, 10 पैसे या 0.01 फीसदी टूटकर 988 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 16657.96 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 20187.63 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5874.20 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 663.56 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 23.81 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 498.25 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 4515.74 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2197.47 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 1.25 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 10602 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 64298 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 19942 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 271240 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 43335 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 8461 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 21509 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 72440 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 20013 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 28178 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल जून 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 138.5 रुपये की बढ़त के साथ 676.3 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 1.55 रुपये की बढ़त के साथ 9.75 रुपये हुआ।

सोना मई 165000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 919.5 रुपये की गिरावट के साथ 744 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 4200.5 रुपये की गिरावट के साथ 2448 रुपये हुआ। तांबा मई 1400 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 10.94 रुपये की गिरावट के साथ 6.37 रुपये हुआ। जस्ता मई 380 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 2.39 रुपये की गिरावट के साथ 0.65 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल जून 8000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 30.5 रुपये की गिरावट के साथ 218 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मई 280 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 2.15 रुपये की गिरावट के साथ 8.65 रुपये हुआ।

सोना मई 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 144 रुपये की बढ़त के साथ 391.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मई 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1152 रुपये की बढ़त के साथ 2010 रुपये हुआ। तांबा मई 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.24 रुपये की बढ़त के साथ 6.51 रुपये हुआ। जस्ता मई 350 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 10 पैसे के सुधार के साथ 2 रुपये हुआ।

सूरत में गर्मी का कहर, सरथाना ज़ू बना राहत का ठिकाना: बाघ तेंदुओं के लिए कूलर, पक्षियों के लिए फव्वारों की खास व्यवस्था

सूरत में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जहां आम लोग लू और उमस से परेशान हैं, वहीं सरथाना नेचर पार्क और ज़ू प्रशासन ने वन्यजीवों को राहत देने के लिए व्यापक और विशेष इंतज़ाम किए हैं। जैसे-जैसे पारा ऊपर चढ़ रहा है, वैसे-वैसे ज़ू के अंदर जानवरों की सुरक्षा और आराम को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी जानवर पर गर्मी का दुष्प्रभाव न पड़े और वे अपने प्राकृतिक व्यवहार को सामान्य रूप से बनाए रख सकें।

बाघ, तेंदुआ, शेर और भालू जैसे बड़े और संवेदनशील वन्यजीवों के लिए इस बार विशेष कूलिंग व्यवस्था की गई है। इनके बाड़ों में कूलर लगाए गए हैं और कई जगहों पर पानी के फव्वारे लगातार चलाए जा रहे हैं। इससे बाड़ों के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और जानवरों को राहत मिलती है। खास बात यह है कि बाघ और तेंदुओं के लिए बड़े पानी के टब रखे गए हैं, जिनमें ठंडा पानी लगातार भरा जा रहा है। कई बार ये जानवर खुद ही इन टबों में बैठकर या लेटकर शरीर को ठंडा करते हैं, जिससे उनकी प्राकृतिक सहजता भी बनी रहती है।

ज़ू प्रशासन के मुताबिक, पूरे परिसर में हरियाली और पानी के छिड़काव पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पेड़ों और घास वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी डाला जा रहा है ताकि वातावरण में नमी बनी रहे और तापमान थोड़ा कम महसूस हो। प्रशासन का कहना है कि इन प्रयासों के कारण ज़ू परिसर का तापमान शहर के औसत तापमान से लगभग दो डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है, जो जानवरों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है।

सरथाना ज़ू में आने वाले पर्यटक भी इस व्यवस्था को देखकर प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग यह देखकर हैरान हैं कि कैसे जानवरों के लिए अलग-अलग तरह की कूलिंग और प्राकृतिक वातावरण जैसी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए यह अनुभव और भी रोचक बन गया है क्योंकि वे जानवरों को पानी में खेलते और गर्मी से राहत लेते हुए देख पा रहे हैं। बाड़ों में रखे गए बड़े टब और लगातार चल रहे

फव्वारे लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और यह ज़ू भ्रमण को और भी खास बना रहे हैं।

ज़ू गाइड हिना पटेल के अनुसार, केवल वातावरण ही नहीं बल्कि जानवरों के खानपान में भी गर्मी के अनुसार बदलाव किया गया है। शाकाहारी जानवरों को तरबूज, खरबूजा, गन्ना और अन्य रसदार फल दिए जा रहे हैं, ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो। पक्षियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे डिहाइड्रेशन से बच सकें। इसके अलावा सभी जानवरों के पीने के पानी में इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाया जा रहा है, जिससे उनके शरीर में पानी और नमक का संतुलन बना रहे और वे स्वस्थ रह सकें।

रात के समय भी विशेष देखभाल की व्यवस्था की गई है। जब दिन ढलने के बाद बाघ, तेंदुए और अन्य शिकारी जानवरों को नाइट शेल्टर में रखा जाता है, तब वहां कूलर और पंखों को लगातार चलाया जाता है। इससे रात के समय भी तापमान नियंत्रित रहता है और जानवर आराम से सो सकते हैं। भालू और शुतुरमुर्ग जैसे जानवरों के बाड़ों में भी फव्वारों की व्यवस्था की गई है, जिससे वे समय-समय पर पानी में खेलते हुए खुद को ठंडा रखते हैं।

ज़ू प्रशासन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल जानवरों को गर्मी से बचाना नहीं है, बल्कि उन्हें तनावमुक्त और प्राकृतिक वातावरण देना भी है। जानवरों की सेहत और व्यवहार पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थाओं में बदलाव भी किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों ने इस पहल की सराहना की है। उनका मानना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं न केवल जानवरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाती हैं बल्कि समाज में पशु संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाती हैं। गर्मी के इस कठिन समय में सरथाना ज़ू का यह प्रयास यह संदेश देता है कि सही देखभाल और प्रबंधन से हर जीव को सुरक्षित और आरामदायक वातावरण दिया जा सकता है।

सूरत स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित

सूरत स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के अंतर्गत प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3 एवं 4 के बीच थ्रू रूफ लॉन्चिंग के कार्य के कारण पश्चिम रेलवे की कुछ ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रभावित ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

शॉर्ट टर्मिनेट / शॉर्ट ओरिजिनेट होने वाली ट्रेनें:-

16 मई, 2026 से 30 मई, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12935 बांद्रा टर्मिनस–सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन उधना एवं सूरत स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

17 मई, 2026 से 29 मई, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20925 सूरत– अमरावती सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। अतः यह ट्रेन सूरत एवं उधना स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

16 मई, 2026 से 30 मई, 2026 तक यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 20926 अमरावती– सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस उधना स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी। अतः यह ट्रेन उधना एवं सूरत स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं।

गुजरात को मिला भारत का पहला सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, अहमदाबाद धोलेरा के बीच बनेगा 134 किमी लंबा ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड कॉरिडोर

20,667 करोड़ की लागत से विकसित होगा देश का पहला स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट — नमो भारत ट्रेनों का होगा संचालन

अहमदाबाद, 15 मई 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने गुजरात को देश का पहला ब्रॉड गेज सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रदान करते हुए अहमदाबाद (सरखेज)–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को ऐतिहासिक मंजूरी प्रदान की है। लगभग 20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना भारतीय रेलवे की पहली स्वदेशी तकनीक आधारित सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना होगी, जिस पर भविष्य में नमो भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

करीब 134 किलोमीटर लंबी यह नई दोहरी रेल लाइन अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (SIR), आगामी धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा लोथल स्थित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (National Maritime Heritage Complex) को अत्याधुनिक रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की डिज़ाइन गति 220 किमी प्रति घंटा तथा परिचालन गति 200 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है। कॉरिडोर पर कुल 13 स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

परियोजना के अंतर्गत 3 मेगा पुल, 74 किलोमीटर वायाडक्ट, 39 रोड अंडर ब्रिज तथा 2 रेल ओवर रेल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। कुल ट्रैक लंबाई लगभग 293 किलोमीटर होगी। परियोजना को अगले 4 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा

"अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना भारत के रेलवे इतिहास में एक नई शुरुआत है। यह केवल एक रेल लाइन नहीं, बल्कि 'न्यू इंडिया' की आधुनिक, तेज और आत्मनिर्भर परिवहन व्यवस्था का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे आत्मनिर्भर भारत के विज़न को नई गति दे रहा है। स्वदेशी तकनीक आधारित यह परियोजना भविष्य में देशभर में सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विस्तार का आधार बनेगी।"

गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार दास ने कहा:

"माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी और माननीय

रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में स्वीकृत यह परियोजना गुजरात के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में नया अध्याय सिद्ध होगी। धोलेरा SIR को साबरमती, धोलेरा एयरपोर्ट एवं लोथल से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर राज्य की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देगा। साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों पर मेट्रो एकीकरण, साबरमती में बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी तथा मौरैया में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ाव गुजरात को विश्वस्तरीय मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगा।"

मंडल रेल प्रबंधक (DRM), अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश ने कहा

"माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी के मार्गदर्शन में भारतीय रेलवे को इस ऐतिहासिक परियोजना के क्रियान्वयन का गौरव प्राप्त हुआ है। 134 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के समानांतर नए संरेखण पर विकसित किया जाएगा। यह परियोजना अहमदाबाद एवं धोलेरा क्षेत्र को विश्वस्तरीय रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे यात्रियों को तेज, सुरक्षित एवं आधुनिक यात्रा सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र में उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार को भी नई गति मिलेगी।"

उन्होंने आगे कहा कि विश्व का पहला ब्रॉडगेज सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर अब गुजरात में बनने जा रहा है। पहली बार दुनिया में कोई सेमी हाई-स्पीड ट्रेन 220 किमी/घंटा की रफ्तार से ब्रॉडगेज ट्रैक पर दौड़ेगी। यह पूरी परियोजना और ट्रेन पूरी तरह मेक इन इंडिया तकनीक पर आधारित होगी। ट्रेन में अत्याधुनिक कवच 5.0 सुरक्षा प्रणाली लगाई जाएगी, जिससे सुरक्षा और ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नया मानक स्थापित होगा। अब तक दुनिया में सेमी हाई-स्पीड ट्रेनें मुख्यतः स्टैंडर्ड गेज पर चलती रही हैं, लेकिन भारत पहली बार ब्रॉडगेज नेटवर्क पर 220 kmph स्पीड का सफल मॉडल विकसित करने जा रहा है। यह सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग, आत्मनिर्भरता और रेलवे आधुनिकीकरण का ऐतिहासिक अध्याय है। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद अहमदाबाद और धोलेरा के बीच यात्रा समय घटकर लगभग 1 घंटे से भी कम रह जाएगा तथा धोलेरा को सीधे अहमदाबाद–मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने में भी सहायता मिलेगी।

परियोजना के प्रमुख लाभ

- लगभग 284 गांवों एवं 5 लाख से अधिक आबादी को प्रत्यक्ष लाभ
- प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख टन अतिरिक्त मालभाड़ा परिवहन क्षमता
- लॉजिस्टिक लागत में प्रतिवर्ष लगभग 54 करोड़ की बचत
- निर्माण चरण में लगभग 91 लाख मानव-दिवस रोजगार सृजन
- लगभग 0.48 करोड़ लीटर ईंधन की वार्षिक बचत
- लगभग 2 करोड़ किलोग्राम CO उत्सर्जन में कमी — जो लगभग 10 लाख पेड़ों के रोपण के बराबर पर्यावरणीय लाभ के समान है
- साबरमती, गांधीग्राम एवं वस्त्रापुर स्टेशनों पर मेट्रो नेटवर्क से एकीकरण
- साबरमती स्टेशन पर बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी
- मौरैया (साणंद) में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तथा भीमनाथ लॉजिस्टिक हब से संपर्क

यह परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना तथा भारत की लॉजिस्टिक दक्षता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। यह कॉरिडोर गुजरात को आधुनिक, हरित एवं उच्च गति परिवहन अवसंरचना के नए युग में प्रवेश कराने वाली ऐतिहासिक पहल सिद्ध होगा।

अप्रैल 2026 में वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत का निर्यात मज़बूती से जारी: फियो अध्यक्ष

नई दिल्ली, 15 मई, 2026: अप्रैल 2026 में भारत के वस्तु निर्यात में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थितियों और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद देश के निर्यात क्षेत्र की मज़बूती और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। अप्रैल 2025 में 38.28 बिलियन डॉलर से बढ़कर अप्रैल 2026 में भारत का वस्तु निर्यात 43.56 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि इसी अवधि में पिछले साल के 65.38 बिलियन डॉलर से आयात तेज़ी से बढ़कर 71.94 बिलियन डॉलर हो गया। अप्रैल 2026 के दौरान भारत के वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात का अनुमान 80.80 बिलियन डॉलर है।

व्यापार डेटा पर टिप्पणी करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइज़ेशन्स (फियो) के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि अप्रैल 2026 में वस्तु निर्यात में हुई वृद्धि, लगातार अनिश्चित होते जा रहे वैश्विक व्यापार माहौल के बीच भारतीय निर्यातकों की अंतर्निहित ताकत और अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करती है। भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों और बढ़ती लॉजिस्टिक्स लागतों के बावजूद, भारतीय निर्यातकों ने प्रमुख क्षेत्रों में मज़बूती से प्रदर्शन करना जारी रखा है।

हालाँकि, अप्रैल 2026 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 28.38 बिलियन डॉलर हो गया। फियो प्रमुख ने कहा कि इस बढ़ते घाटे का मुख्य कारण मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष है, जिसने वैश्विक शिपिंग मार्गों को बाधित किया है, वस्तु ढुलाई और ऊर्जा लागतों को बढ़ाया है, और भारत के आयात बिल पर काफ़ी असर डाला है। श्री रल्हन ने आगे कहा कि आयात में हुई तेज़ वृद्धि—विशेष रूप से पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में—और मध्य पूर्व संघर्ष के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों ने भी व्यापार घाटे के बढ़ने की समस्या को और बढ़ा दिया है। हालाँकि, वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात का 80.80 बिलियन डॉलर के मज़बूत स्तर पर होना यह संकेत देता है कि भारत का बाहरी क्षेत्र अभी भी एक स्थिर स्थिति में बना हुआ है।

श्री रल्हन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा क्षेत्र निर्यात वृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये वैश्विक बाज़ारों में भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमताओं और विविधीकरण को दर्शाते हैं।

अप्रैल 2026 के दौरान भारत के मुख्य निर्यात आइटमों में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन, रत्न और आभूषण, सभी तरह के कपड़ों से बने रेडीमेड गारमेंट्स (आरएमजी), चावल, सूती धागा/कपड़ा/बने-बनाए सामान/हथकरघा उत्पाद और प्लास्टिक व लिनोलियम उत्पाद शामिल थे। वहीं, भारत के मुख्य आयात आइटमों में कच्चा पेट्रोलियम और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और नॉन-इलेक्ट्रिकल), परिवहन उपकरण, अलौह धातुएँ, कोयला/कोक/ब्रिकेट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रसायन, कृत्रिम रेज़िन/प्लास्टिक सामग्री और वनस्पति तेल शामिल थे।

अप्रैल 2026 के दौरान भारत के लिए मुख्य निर्यात गंतव्य अमेरिका, सिंगापुर, यूएई, चीन, बांग्लादेश, नीदरलैंड, तंजानिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका थे; जबकि मुख्य आयात स्रोत चीन, रूस, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी और इंडोनेशिया थे।

श्री रल्हन ने आने वाले महीनों में निर्यात की गति को बनाए रखने के लिए निर्यातकों को लगातार नीतिगत सहायता, स्थिर लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखलाओं और बेहतर बाज़ार पहुँच पहलों की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने दोहराया, "आगे बढ़ते हुए, भारत को लगातार निर्यात वृद्धि हासिल करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाने के लिए निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, व्यापार सुविधा और रणनीतिक व्यापार साझेदारियों को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए।"

सोने के आयात में वृद्धि से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है, सरकारी उपायों के बावजूद आम आदमी पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत बहुमूल्य धातुओं का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। कच्चे तेल के बाद देश के आयात में सोने का हिस्सा सबसे अधिक है। बढ़ती मांग और आयात के कारण विदेशी मुद्रा की खपत भी बढ़ गई है। इसी वजह से रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। आभूषण व्यापारी सरकार के इस कदम से निराश हैं, लेकिन यह भी सच है कि यदि समय रहते उचित उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले दिनों में उत्पन्न होने वाली सबसे खराब स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पश्चिम एशियाई संकट को देखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग, खाना पकाने के तेल की खपत में कमी और सोने की खरीद एवं विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने का आग्रह किया है ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। इससे यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है और इसे कम करने के लिए वैकल्पिक उपाय करने होंगे। इसके बाद सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% करने की घोषणा की गई। इसके चलते इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में भारी उछाल आया। दूसरे, आभूषण क्षेत्र में 5 लाख से अधिक कारीगर कार्यरत हैं, उनके रोजगार का भी ध्यान रखना आवश्यक था। इसके अलावा, भारत के विदेशी मुद्रा संसाधनों का उपयोग तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल और रक्षा आवश्यकताओं जैसे आवश्यक आयातों को प्राथमिकता देने के लिए किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से गैर-जरूरी ईंधन का उपयोग कम करने का आग्रह किया था। इसके बाद उन्होंने स्वयं अपने वाहनों की संख्या कम कर दी। हालांकि, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि यह सरकारी अभियान केवल दिखावटी विज्ञापनों तक सीमित न रहे। यदि जन प्रतिनिधि भी इसमें भाग लें, तभी जनता इस उपाय को व्यापक रूप से स्वीकार करेगी। अन्यथा, अगर शेठ की शिक्षाओं का अनुसरण करने का भी ऐसा ही हश्र हो तो आश्चर्य की बात नहीं होगी।

विश्व पर्यावरण दिवस अभियान 2026 के अंतर्गत भावनगर मंडल में पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई गई

भारतीय रेल द्वारा 15 मई से 5 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के शुभारंभ अवसर पर शुक्रवार, 15 मई 2026 को भावनगर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री ऋत्विक शर्मा ने मंडल कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता तथा प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने हेतु प्रतिज्ञा दिलाई।

शपथ के माध्यम से सभी उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने, जल एवं ऊर्जा की बचत करने, प्लास्टिक के उपयोग को कम करने, स्वच्छता बनाए रखने तथा हरित एवं सतत जीवनशैली

अपनाने का संकल्प लिया।

यह अभियान भारतीय रेल द्वारा भारतीय रेलवे के समस्त मंडलों एवं कार्यशालाओं में 15 मई से 5 जून 2026 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा मिशन लाइफ के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाना है। इस अवधि के दौरान जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं ऊर्जा संरक्षण तथा हरित परिचालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

भावनगर मंडल पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा इस अभियान के माध्यम से कर्मचारियों एवं आमजन में पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा 16/17 मई, 2026 को रात्रिकालीन ब्लॉक

पश्चिम रेलवे द्वारा 15/16 मई, 2026 तथा 16/17 मई, 2026 की मध्यरात्रि के दौरान उपनगरीय खंड पर मेजर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक दादर स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कमीशनिंग कार्य तथा नायगांव स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज के गर्डरों की लॉन्चिंग के लिए लिया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दादर स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के कमीशनिंग हेतु 15 मई, 2026 को 23:00 बजे से 16 मई, 2026 को 06:00 बजे तक 5वीं लाइन तथा अप एवं डाउन फास्ट लाइनों पर ब्लॉक लिया जाएगा।

इसी प्रकार, नायगांव स्टेशन पर रोड क्रेन की सहायता से फुट ओवर ब्रिज के दो स्पैन के गर्डरों की लॉन्चिंग हेतु 16/17 मई, 2026 की मध्यरात्रि में अप एवं डाउन स्लो लाइन पर 01:00 बजे से 04:00 बजे तक तथा अप

एवं डाउन फास्ट लाइन पर 02:30 बजे से 03:30 बजे तक ब्लॉक लिया जाएगा।

ब्लॉक अवधि के दौरान सभी फास्ट लाइन की ट्रेनें मुंबई सेंट्रल और सांताक्रूज़ स्टेशनों के बीच स्लो लाइनों पर चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सभी डाउन स्लो लाइन की ट्रेनें भायंदर और वसई रोड स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर चलाई जाएंगी। साथ ही, ब्लॉक के कारण कुछ उपनगरीय सेवाएं निरस्त रहेंगी। प्रभावित उपनगरीय सेवाओं की विस्तृत जानकारी उपनगरीय खंड के स्टेशन मास्टरों के पास उपलब्ध रहेगी।

निम्नलिखित मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें प्रभावित:

- 15 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19016 पोरबंदर–दादर सौराष्ट्र एक्सप्रेस को बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।
- 16 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12927 दादर–एकता नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बोरीवली स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी तथा 17 मई, 2026 को अपने निर्धारित समयानुसार प्रस्थान करेगी।
- 17 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 19003 दादर–भुसावल खानदेश एक्सप्रेस बोरीवली स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी।
- 16 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22946 ओखा–दादर सौराष्ट्र मेल को ओखा से 2 घंटे 15 मिनट रेगुलेट किया जाएगा तथा इसे बोरीवली स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा।
- 16 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 09052 भुसावल–दादर स्पेशल को भुसावल से 1 घंटे के लिए रेगुलेट किया जाएगा।
- 16 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 12928 एकता नगर–दादर एक्सप्रेस को प्रारंभिक स्टेशन से 1 घंटा 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।
- 16 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 14707 हनुमानगढ़–दादर एक्सप्रेस को सूरत और विरार स्टेशनों के बीच 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।
- 17 मई, 2026 को यात्रा प्रारंभ करने वाली ट्रेन संख्या 22953 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस को मुंबई सेंट्रल से 30 मिनट रेगुलेट किया जाएगा।
- यात्रियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त परिवर्तनों को ध्यान में रखें और तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं।
- रविवार, 17 मई, 2026 को पश्चिम रेलवे के उपनगरीय खंड पर दिवसकालीन ब्लॉक नहीं रहेगा।